भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2947

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

पिछड़े और ग्रामीण जिलों में डिजिटल सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए विशेष पहल

2947. श्री अ. मनिः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक केन्द्रित डिजिटल सेवाओं के विस्तार के माध्यम से पिछड़े और ग्रामीण जिलों विशेषकर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए कोई विशेष पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान धर्मपुरी जिले में डिजिटल कनेक्टिविटी, फाइबर अवसंरचना और ग्रामीण डिजिटल परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने धर्मपुरी जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को सुदृढ़ करने, ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को आसान बनाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या धर्मपुरी जिले में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, लास्ट माइल डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं की घर-घर तक पहुँच में सुधार करने के लिए कोई अतिरिक्त परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।
सरकार देश भर में कुशल, पारदर्शी और सुलभ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू कर रही है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी पात्र नागरिकों के लिए डिजिटल अवसंरचना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित है। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:
इंटरनेट कनेक्टिविटी: डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है।

- **दूरसंचार, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 133+ करोड़ हो गए। तमिलनाडु में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या 8.41 करोड़ को पार कर गई है।
- इंटरनेट ग्राहक मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गए। तमिलनाडु में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या 6.90 करोड़ को पार कर गई है।

- **भारतनेट - गांवों को इंटरनेट से जोड़ना:** जून 2026 तक, देश में भारतनेट परियोजना के तहत लगभग 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा हेतु तैयार किया गया है। तमिलनाडु में 9,280 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, जिनमें धरमपुरी में 210 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित 4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत, जून 2026 तक, तमिलनाडु में 257 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।
- 30.06.2026 तक, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) वित्त पोषित मोबाइल योजना के तहत देश भर में 24,784 टावर चालू किए गए हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित तमिलनाडु राज्य की स्थिति इस प्रकार है:

	टावर्स प्लान्ड	विलेजेस प्लान्ड	टावर्स ऑन एयर	कवर किए गए गांव
तमिलनाडु	356	445	257	308
धर्मपुरी जिला	14	22	11	19

- 30.06.2026 तक, तमिलनाडु में डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की विभिन्न चल रही परियोजनाओं के तहत कुल 1886 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से सेवाओं का वितरण: किफायती डेटा, सहायक डिजिटल एक्सेस प्वाइंट और इंटरऑपरेबल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा लागत 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।

- **आधार:** आधार ने सुरक्षित और तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए एक विश्वसनीय बायोमेट्रिक पहचान मंच बनाया है। 1.44+ बिलियन से अधिक आधार नंबर तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु में 8.18 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी):**आधार से जुड़ी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 318 योजनाएं) से प्राप्त नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। देशभर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन को काफी बढ़ावा मिला है।
  - यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।
  - भारत में होने वाले 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 50% रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से होते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिलावार यूपीआई आंकड़े https://www.npci.org.in/product/ecosystem-statistics/upi पर उपलब्ध हैं।
- **डिजिलॉकर** नागरिकों को मूल जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक कभी भी पहुंच प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म पर 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिनमें 2,822 पंजीकृत जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज शामिल हैं। तमिलनाडु राज्य में डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 2.18 करोड़ से अधिक आधार-सक्षम पंजीकरण हो चुके हैं।

- **यूनिफ़ाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस (उमंग)** नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा एकीकृत 17 सेवाएं शामिल हैं।
- **ई-संजीवनी** आपके स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने तमिलनाडु राज्य में 4 करोड़ से अधिक परामर्श सहित देश भर में 48 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा की है।
- डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) – **भाषिनी** शुरू किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है।

सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी में सहयोग

सामान्य सेवा केंद्र – सीएससी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। मई 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.01 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 3.91 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्यरत हैं।

तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान में 18,240 सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 12,112 सीएससी शामिल हैं। धर्मपुरी जिले में, 498 सीएससी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिनमें 412 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर हैं।

डिजिटल कौशल का निर्माण: भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल पहुंच तक सीमित नहीं है; यह लोगों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और देश भर में नागरिकों को सक्षम बनाने पर केंद्रित है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है (6 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष)। तमिलनाडु राज्य में, इस योजना के तहत 14+ लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें धर्मपुरी जिले के 64,813 अभ्यर्थी शामिल थे। यह योजना 31.03.2024 को समाप्त हो गई है।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम**, भारत सरकार और नैसकॉम की एक सहयोगी पहल, उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करती है। अब तक, 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 23 लाख से अधिक ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया है, जिसमें तमिलनाडु के 5.81 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)** देश भर में 56 केंद्रों और 9,000 से अधिक भागीदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नाइलिट द्वारा 31.92 लाख+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। नाइलिट की चेन्नई में अपने केंद्र और राज्य भर में 35+ भागीदार संस्थानों के माध्यम से तमिलनाडु में मजबूत उपस्थिति है। पिछले 03 वर्षों में, नाइलिट ने तमिलनाडु राज्य में 37500+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/कुशल बनाया है।
- **नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म:** यह प्लेटफॉर्म उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक 2.75 लाख+ अभ्यर्थियों ने नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।

उपरोक्त के अलावा, प्रमाण पत्र जारी करने, पेंशन से संबंधित सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी सेवाएं राज्य सरकार के पोर्टलों और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी (टीएनईजीए) ने ई-सेवा पोर्टल विकसित किया है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नागरिक-केंद्रित सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की एंड-टू-एंड ऑनलाइन डिलीवरी को सक्षम बनाता है। डिजिटल सेवाओं को https://www.tnesevai.tn.gov.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

बजट आवंटन और उपयोग: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने बजटीय प्रावधान हैं। एमईआईटीवाई कार्यक्रम के तहत आठ केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजनाओं को लागू करता है, जिसके लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है।

*****